राजेश कुमार,-याचिकाकर्ता

बनाम

निहाल चंद और अन्य, -प्रतिवादी

आपराधिक विविध. नहीं। 7448/एम 2005

15 दिसंबर 2006

2007(2)

भारतीय दंड संहिता, 1860—एस. 439(2)—एक महिला अपराध कर रही है, शादी के 5 साल बाद आत्महत्या-एफ.आई.आर. धारा 304-बी/34आईपीसी के तहत-मृतक मृत्यु पूर्व बयान में स्वीकार किया कि उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला था और किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता - ट्रायल कोर्ट मृत्यु पूर्व घोषणापर निर्भर है ,जमानत देने की घोषणाट्रायल कोर्ट दे रहा है, जमानत देते समय विस्तृत और व्यापक कारण - कोई विकृति नहीं, जमानत की याचिका खारिज आदेश-रद्द करने के लिए कोई ठोस या भारी कारण नहीं बताया गया है |

माना गया, कि वर्तमान एफ.आई.आर. में आरोप खुलासा होगा , अपराध जघन्य है लेकिन सत्र न्यायालय नेजमानत की रियायत देते समय विस्तृत कारण बहुत विस्तार से बताया है और। यह आदेश कथित तौर पर इस आधार पर गलती नहीं की जा सकती कि यह एक बिना कारण जमानत आदेश देना है | याचिकाकर्ता का मूल आरोप यह आग्रह करना है,इस मामले में पारित आदेश इस आधार पर मनमाना है कि कोर्ट ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर गलत भरोसा किया है। इसके बाद से दस्तावेज़ चालान का हिस्सा बन रहा है, इसे बनाना उचित नहीं होगा| इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर कोई टिप्पण भी नहीं हो सकता है | इस स्तर पर यह मामले की खूबियों को छूने जैसा है जिससे बचा जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ और इसे साबित करना पार्टियों पर निर्भर है, ट्रायल कोर्ट के समक्ष जब मुकदमा शुरू होता है सबूतों के आधार पर या तो भरोसा किया जाएगा या खारिज कर दिया । हालाँकि, इस पर चरण में, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी किसी भी सामग्री को नजरअंदाज किया जाना था या विचार नहीं किया जाना था, ऐसा कहना संभव नहीं होगा इस सामग्री पर विचार करने के परिणामस्वरूप आदेश मनमाना हो गया है या गैरकानूनी। आक्षेपित आदेश में कोई विकृति नहीं देखी गई है। कथित मृत्यु पूर्व बयान में मृतिका ने कहा है कि उसने पानी डाला था, केरोसीन स्वयं और किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोई ठोस या जबरदस्त नहीं, जमानत रद्द करने के लिए कारण बताए गए हैं।

रणजीत सिंह, जे.

(1) यह आदेश 20(^5, 24616- के सीआरएम संख्या 7448-एम का निपटान करेगा) 2005 का एम और 2005 का 41927-एम।

(2) ये याचिकाएं जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई हैं , संबंधित उत्तरदाताओं नानक चंद, जीवनी देवी को दी गई| पवन गुप्ता. एफ.आई.आर. क्रमांक 271 धारा 304-बी/34 आईपीसी के तहत था | 2004 फूल चंद याचिकाकर्ता के कहने पर 3 दिसंबर को पुलिस स्टेशन ताओरू, जिला गुड़गांव में पंजीकृत किया गया।वह सुषमा नाम की अभागी लड़की एक के पिता हैं, जिसकी शादी पवन कुमार से हुई थी | 2 दिसम्बर 1999 को ताओरू गांव में दहेज का मामला बताया गय| |शिकायतकर्ता की क्षमता के अनुसार दिया गया लेकिन फिर भी उत्तरदाताओं का परिवार संतुष्ट नहीं था और उन्होंने मांगें उठाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बेटी आत्महत्या कर ले| दहेज सामग्री का विवरण देते हुए शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर उत्तरदाताओं द्वारा मांग की गई |खुलासा किया कि 2 दिसंबर 2004 को जो 'शादी' थी,अपनी बेटी की सालगिरह पर, उन्हें एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ | उनके दामाद पवन कुमार के पास वह बकाया रुपये थे। अगला सुबह, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर उसका एक टेलीफोन कॉल आया कि उसका पति दबाव में कुछ लिखना चाहता था और रात करीब 10 बजे शिकायतकर्ता शेष राशि भेज दे| शिकायतकर्ता को उसके दामाद से संदेश मिला कि उसकी बेटी अस्पताल में था| ताओरू सरकारी अस्पताल पहुंचे

शिकायतकर्ता सुषमा जली हुई हालत में मिली, जहां से उसे गुडगाँव रेफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार वह के घर गया था ,उत्तरदाताओं ने घटना के बारे में कुछ कहानी बताने वाले निशान देखे हैं | अपनी बेटी को जलाने का और तदनुसार वर्तमान एफ.आई.आर. उसके द्वारा दर्ज कराया गया। चूंकि सुषमा अंदर ही अंदर अप्राकृतिक मौत मर चुकी थी |उसकी शादी के सात साल की अवधि, धारा के तहत मामला 304-बी आईपीसी दर्ज किया गया। हालाँकि, विरोध किये जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध भी जोड़ा गया | याचिका में खुलासा किया गया कि नानक चंद और पवन कुमार 22 दिसम्बर 2004 को गिरफ्तार कर लिया गया थे | जबकि जीवनी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 जनवरी, 2005 को शिकायत यह है कि शेष आरोपी नहीं थे, आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण गिरफ्तार किया गया। ये भी खुलासा किया कि गिरफ्तारी के बाद भी नानक चंद भर्ती रहे , अतिरिक्त सत्र द्वारा जमानत पर रिहा होने तक 15 जनवरी, 2005 को न्यायाधीश, गुड़गांव, जो इसमें विवादित है। मामला यह है कि जांच बिल्कुल शुरुआती चरण में थी एफ.आई.आर. में लगाए गए गंभीर आरोपों से बेपरवाह जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत की रियायतें दे । जब यह जमानत मंजूर की गई, तब चार आरोपी अभी बाकी थे इन सभी तथ्यों का संदर्भ देते हुए आग्रह किया गया है कि इससे विवेक के मनमाने प्रयोग का पता चलेगा, जो नहीं हो सकता,विवेकपूर्ण कहा गया है। द्वारा जमानत की रियायत के दुरुपयोग का आरोप नानक चंद और उनके बेटे भारत भूषण उर्फ बंटी के पास भी है | यह खुलासा करके बनाया गया कि उन्होंने याचिकाकर्ता को खुलेआम धमकी दी थी और मामले की पैरवी बंद करने को कहा जा रहा है. संदर्भ भी दिया गया है ,18 तारीख के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी कुछ खबरों के लिए बनाया गया

(3) इसके बाद जीवनी देवी और पवन कुमार भी थे, 10 तारीख को गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत दे दी , उपरोक्त उल्लिखित आपराधिक याचिकाओं में निहित समान आधारों पर क्रमशः फरवरी, 2005 और 8 जून, 2005 को चुनौती दी गई। इन याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किये गये थे, जवाब दाखिल कर दिए गए हैं | उत्तरदाताओं की ओर से. उन्होंने आक्षेप का खंडन किया है, याचिकाओं में लगाए गए आरोपो के आदेश को सही ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संबंधितों की रिहाई का निर्देश दिय।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बलदेव सिंह ने बहुत ज़ोर देकर कहा है कि वर्तमान मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है | जमानत देने में विवेक का गलत और अवैध उपयोग उत्तरदाताओं उन्होंने आगे रियायत के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है| उत्तरदाताओं द्वारा जमानत की और तदनुसार जमानत प्रस्तुत की है, उत्तरदाताओं को दी गई अनुमति को रद्द करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि अतिरिक्त सत्र द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया न्यायाधीश का यह आदेश मनमाना और अवैध है, जो कि रहा है | बिना कोई ठोस कारण बताए पारित कर दिया गया और यह उचित है, हस्तक्षेप किया जाए की कार्रवाई पर वह गंभीर आपत्ति जताएंगे | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कथित तौर पर मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा किया, जो मृतका सुषमा द्वारा निर्मित बताया गया है |एक डॉक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया और केवल 20 दिनों के बाद दिन का उजाला देखा गया। वकील, ऐसे में, न्यायालय से आग्रह करेंगे निर्मित किए जा रहे दस्तावेज़ के इस पहलू की सराहना करने के बजाय इस पर भरोसा किया है और अवैध खुलासा करने वाले उत्तरदाताओं को जमानत दे दी है |

(5) श्री आर.एस. चीमा, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील, दूसरी ओर, सभी प्रस्तुतियाँ का खंडन करेगा बताया कि जब यह घटना हुई तब यह शादी पांच साल पुरानी थी। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि यद्यपि उसका पूरा परिवार उत्तरदाता शामिल थे लेकिन जांच के बाद, केवल तीन व्यक्ति (5) श्री आर.एस. चीमा, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील, वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूरा परिवार उत्तरदाता शामिल थे लेकिन जांच के बाद, शिकायतकर्ता द्वारा नामित सात में से केवल तीन व्यक्ति चालान कर दिया गया है। । इशारा करते हुए कानूनी स्थिति से बाहर, श्री चीमा आग्रह करेंगे कि यह केवल विकृत है, जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप और उस पर विचार की आवश्यकता हो सकती है | एक बार दी गई जमानत को रद्द करने के लिए जमानत देने के मामले एक से बिल्कुल अलग हैं, जो प्रासंगिक हैं। वकील के अनुसार, याचिका में लगाया गया आक्षेपित आदेश में विकृति दिखाई नहीं देती है, विद्वान वकील को कुछ नहीं दिखेगा याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों के विपरीत

न्यायालय में मृत्युपूर्व कथन पर भरोसा करना गलत है, जिसे आर2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एनेक्सचर पी2 का हवाला देते हुए श्री चीमा कहेंगे कि मृत्यु पूर्व घोषणा बनाते समय इस संबंध में शिकायत पर याचिकाकर्ता ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई |

(6) जमानत रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता के वकील पूरन बनाम राम बिलास और दूसरा (1) के मामले पर बहुत मजबूत निर्भरता रखी है | यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपील दायर की गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त सत्र द्वारा उक्त मामले में याचिकाकर्ता को दी गई। जबकि उच्च द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया | न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियाँ की थीं, जिसे कानूनी तौर पर जमानत रद्द करने पर विचार किया जा सकता है । इसी सन्दर्भ में विद्वान वरिष्ठ श्री बलदेव सिंह जी ने कहा और वकील ने आग्रह किया है कि विवेक का मनमाना और गलत प्रयोग किया जाए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुधार किया जाना चाहिए। जैसा कि वकील ने बताया, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आधार पर गौर किया है | जमानत रद्द करने के लिए सामग्री की अनदेखी की जाएगी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य, जमानत देने का एक विकृत आदेश पारित किया गया है। इस तरह का जघन्य अपराध और वह भी बिना कोई कारण बताए चालान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा नामित सात में से। ओर इशारा करते हुए कानूनी स्थिति से बाहर, श्री चीमा आग्रह करेंगे कि यह केवल विकृत है, जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप और उस पर विचार की आवश्यकता हो सकती है| एक बार दी गई जमानत को रद्द करने के लिए जमानत देने के मामले एक से बिल्कुल अलग हैं, जो प्रासंगिक हैं । वकील के अनुसार याचिका में लगाया गया आरोप आक्षेपित आदेश में विकृति दिखाई देती है, जो कि है भी नहीं विद्वान वकील को कुछ नहीं दिखेगा न्यायालय में मृत्युपूर्व कथन पर भरोसा करना गलत है , जिसे आर2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है | माननीय द्वारा ऐसे आदेश को कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय और न्याय के हित की भी आवश्यकता होगी, ऐसे विकृत आदेश को रद्द किया जाए और जमानत रद्द की जाए। आगे देखते हुए यह याद रखना होगा कि ऐसे अपराध होते हैं, यह वृद्धि पर है और समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव डाल रहा है, यह माना गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक का मनमाना और गलत प्रयोग ठीक करना होगा | माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी हवाला दिया गया, विभिन्न अन्य मामले जमानत रद्द करना जो विचार को विनियमित करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ हो सकती हैं और एक नोटिस की आवश्यकता है और ये हैं:-

"इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सेटिंग की अवधारणा एक तरफ अनुचित अवैध या विकृत आदेश पूरी तरह से पर जमानत रद्द करने की अवधारणा से अलग आधार यह है कि अभियुक्त ने स्वयं कदाचार किया है या कुछ नये तथ्यों के कारण ऐसे रद्दीकरण की आवश्यकता है। यह गुरचरण सिंह मामले में इस न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है |

(7) माननीय गुरुचरण सिंह के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दृष्टिकोण यह देखना चाहिए कि क्या जमानत देने का आदेश किसी गंभीर अक्षमता के कारण शुरू किया गया था, यह न्याय के हित में उच्च न्यायालय के लिए सही और उचित है । यह ध्यान देने योग्य है, जैसे कि मूलतः विकृति होगी जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार बनें।

(8) श्री बलदेव सिंह फिर जगन के एक मामले का उल्लेख करेंगे नाथ बनाम हरियाणा राज्य (2) जहां सत्र द्वारा जमानत दी गई, ऐसी ही परिस्थितियों में न्यायाधीश, सिरसा को रद्द कर दिया गया था। जबकि जमानत को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए की गंभीरता, प्रकृति और चरित्र तथा तथ्य के प्रति भी उत्तरदाताओं के घर में अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी, सत्र न्यायाधीश ने रिहा करने में अपने विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया प्रतिवादी जमानत पर हैं। हालाँकि, श्री चीमा इसका प्रतिकार करेंगे, माननीय सर्वोच्च द्वारा निर्धारित कानून का हवाला देकर स्थिति दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में न्यायालय, (3) जहां इसन्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आदेश पारित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग। श्री चीमा ने भी रखा है,

सुभेंदु मिश्रा बनाम सुब्रत कुमार मिश्रा पर निर्भरता और दूसरा, (4) भागीरथसिंह जुडेजा बनाम गुजरात राज्य (5) और पूरन का मामला (सुप्रा), जिसे वकील द्वारा संदर्भित किया गया था |

(9) गैर जमानती मामले में जमानत खारिज होना कोई विवाद की बात नहीं है ,प्रारंभिक चरण में और पहले ही दी गई जमानत को विभिन्न आधारों पर विचार और निपटारा दोलत राम (सुप्रा) के मामले में किया जाना रद्द कर दिया गया है । यह एक ऐसा मामला था जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक ने एक अपराध के मामले में जमानत दे दी थी, धारा 304-बी आईपीसी जिसे इस न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। हरियाणा बनाम दोलत राम (6) जिसे निरस्त करते हुए आदेश पारित किया गया, इस न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:-

"प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और पहले से दी गई जमानत को रद्द करना होगा विभिन्न आधारों पर विचार और निपटारा किया गया। बहुत ही ठोस और किसी आदेश के लिए जबरदस्त परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, पहले ही दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश दिया। सामान्यतया, जमानत रद्द करने का आधार, मोटे तौर पर (चित्रात्मक और संपूर्ण नहीं) हैं: हस्तक्षेप या प्रशासन के उचित कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास करें, न्याय से बचना या नियत प्रक्रिया से बचने का प्रयास करना, न्याय या अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग किसी भी तरीके से आधार पर न्यायालय की संतुष्टि की संभावना के रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की आरोपी का फरार होना इसे सही ठहराने वाला एक और कारण है जमानत रद्द करना. हालाँकि, एक बार जमानत मिलनी चाहिए, बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाएगा, इस पर विचार करते हुए कि क्या कोई पर्यवेक्षणीय परिस्थितियाँ हैं ,इसे अनुमति देना अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं रह गया है, रियायत का आनंद लेकर अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने का आरोप लगाया ,मुकदमे के दौरान जमानत की।"

(10) इस प्रकार, बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ हैं, पहले से ही जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए आवश्यक । जैसा कि देखा गया है, आम तौर पर रद्द करने का आधार बताया जाता है, न्याय का या किसी भी मामले में आरोपी को दी गई रियायत का दुरुपयोग जमानत मोटे तौर पर हस्तक्षेप या उचित समय से बचने का प्रयास है। जैसा कि पुराण के मामले (सुप्रा) में एक ऐसा आधार माना गया है | जमानत रद्द करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब सामग्री की अनदेखी की जाए, रिकॉर्ड पर सबूत है कि इस तरह का जघन्य अपराध और वह भी बिना कोई कारण बताए। इसमें कोई संदेह नहीं, वर्तमान एफ.आई.आर. में आरोप अपराध का खुलासा करेंगे ,जघन्य हो लेकिन सत्र न्यायालय ने बहुत विस्तार से बताया है, जमानत की रियायत देते समय कारण यह आदेश कथित तौर पर इस आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता कि यह जमानत देने का आदेश है, बिना किसी कारण के यहां तक कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी मुख्य रूप से आग्रह किया कि यह विवेक का एक अवैध और मनमाना प्रयोग था | इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा इसे ठीक किया जाना आवश्यक है। मुख्य जोर वकील का कहना था कि सेशन कोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित करने में मृत्युपूर्व घोषणा गलत तरीके से भरोसा किया ह। यह दस्तावेज़, जैसे वकील के अनुसार, उत्तरदाताओं का सबसे बचाव था, इस रूप में देखा जाना आवश्यक है। वकील ने यह भी आग्रह किया है कि पुलिस पवन जैसे आरोपी प्रतिवादी की मदद कर रही है | कुमार एक वकील हैं. श्री चीमा ने आदेश की ओर इशारा किया है, मृत्यु पूर्व बयान चालान का हिस्सा बन रहा है और इस प्रकार है| न्यायालय के समक्ष और इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है, जमानत आदि का अनुदान, उन्होंने बताया है कि जिस डॉक्टर के पास था| मृत्यु पूर्व बयान दर्ज कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और उचित जांच के बाद दोषमुक्त कर दिया गया। वकील आकर्षित करेगा माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से समर्थन भागीरथसिंह जुडेजा (सुप्रा) का मामला यह कहने के लिए कि यहां तक कि जहां ए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर न्यायालय का रुख किया गया | जमानत का मामला यह नहीं है कि आरोपी को हिरासत में लिया जाए, सज़ा लेकिन क्या होगी आरोपियों की मौजूदगी परीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध है या उसके विवेक का दुरुपयोग करने की संभावना है, सबूतों से छेड़छाड़ कर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया।सुभेंदु में मिश्रा के मामले (सुप्रा) को विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया | उत्तरदाताओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं | दोलत राम के मामले में (सुप्रा) को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए |इस मामले में जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी

गई | अस्थिर. दोलत राम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण (सुप्रा) कि बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ हैं| पहले से ही जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए आवश्यक है, मंजूरी को सुभेंदु के मामले में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था।

(11) याचिकाकर्ता का मूल आरोप यह आग्रह करना है कि इस मामले में पारित आदेश इस आधार पर मनमाना है कि न्यायालय मृत्यु पूर्व बयान पर गलत भरोसा किया है। इस दस्तावेज़ के बाद से एहलान का हिस्सा बन रहा है, इसे बनाना उचित नहीं होगा, इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करें। वह रकम भी हो सकती है ,मामले की खूबियों को छूने से बचना चाहिए। इस दस्तावेज़ को साबित करना पार्टियों का काम है और वे ऐसा करेंगे भी पहले दिए गए सबूतों के आधार पर या तो भरोसा किया जा सकता है या खारिज कर दिया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट जब मुकदमा शुरू होता है। हालाँकि, इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी किसी भी सामग्री को सुविचारित करने के लिए नजरअंदाज किया जाना था या नहीं। इस पर विचार करना अभी संभव नहीं होगा, इस सामग्री के परिणामस्वरूप आदेश मनमाना या अवैध हो गया है। यह है अन्यथा श्री चीमा ने सही कहा कि कोई आरोप नहीं है, याचिका में कहा गया है कि विवादित आदेश किसी भी तरह से विकृत है। ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 439 (2) Cr. पी.सी. बिजली प्रदान करता है| जमानत रद्द करना और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि उपयुक्त मामले में ऊपर देखे गए विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है।आक्षेपित आदेश में कोई विकृति नहीं देखी गई है। कथित में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में मृतिका ने कहा है कि उसने मिट्टी का तेल डाला था, खुद को और किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोई ठोस या जबरदस्त कारण नहीं जमानत रद्द करने का मामला बनता है। अपराध की गंभीरता, दोलत राम के मामले में जमानत रद्द करने में कारण के रूप में उन्नत किया गया (सुप्रा) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी नहीं मिली| यह देखा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इसे नजरअंदाज कर दिया है, गैर जमानती मामले में जमानत खारिज करने के लिए प्रासंगिक कारकों का भेद प्रथम दृष्टया और पहले से दी गई जमानत को रद्द करना। आदेश जगन नाथ (सुप्रा) के मामले में जमानत रद्द करने पर भरोसा किया गया | याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत रद्द कर दी, गंभीरता और साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप हो। विवादित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कानून के तहत पर्याप्त आधार बनाए गए हैं |

(12) ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र